

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3806] No. 3806] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2018/आश्विन 4, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2018/ASVINA 4, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2018

का.आ. 4984(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, 'उत्तराखंड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण', देहरादून जोकि उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित निकाय है, को उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:-

- (क) सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान
- (ख) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्राप्त पंजीकरण शुल्क;
- (ग) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन शुल्क;
- (घ) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 में दिए गए प्रावधानों के उल्लघंन के लिए जुर्माना;
- (ड़) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्राप्त विलंब शुल्क;
- (च) सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;
- (छ) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के खंड 75(1)(ग) के अनुसार उपर्युक्त राशियों पर उपार्जित ब्याज।

5648 GI/2018 (1)

- 2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'उत्तराखंड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण', देहरादून -
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) कार्यकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।
- 3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 57/2018/ फा. सं. 300196/41/2018-आईटीए-।]

विनयशील गौतम, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापनः यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2018

- **S.O.** 4984(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority', Dehradun, an authority constituted by the Government of Uttarakhand, in respect of the following specified income arising to that authority, namely:-
 - (a) Grants-in-aid received from Government;
 - (b) Registration fees received under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016;
 - (c) Application fees received under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016;
 - (d) Penalties for violation of provisions contained in the Real Estate (Regulation and Development) Act,
 - (e) Late fees received under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016;
 - (f) Fees received under the Right to Information Act, 2005;
 - (g) Interest accrued on above amounts as per clause 75(1)(c) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016.
- 2. This notification shall be effective subject to the conditions that Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority, Dehradun,-
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2018-2019 and shall apply with respect to the assessment years 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-2023.

[Notification No. 57/2018/F.No.300196/41/2018-ITA-I]

VINAY SHEEL GAUTAM, Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.